Now, Short Notice Question. Shri Venkaiah Naidu. ...*(Interruptions)*... Short Notice Question.

SHORT NOTICE QUESTION

Downgrading of 1001 Variety of Paddy

†308. SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India has decided to downgrade the 1001 variety of paddy;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that 1001 variety of paddy was treated as super fine category till this year;

(d) whether Government have received representations from MPs, fanners organisation of Andhra Pradesh, in this regard; and

(e) if so, the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. MTU 1001 variety of paddy grown in Andhra Pradesh was classified in May, 1995 as 'Fine' variety. Following regrouping of earlier three groups to two groups *viz.* "Grade 'A'" and "Common" since Kharif Marketing Season 1997-98, this variety now falls under "Grade 'A'" category.

(d) and (e) No, Sir. However, representations have been received from the Government of Andhra Pradesh and some Members of Parliament seeking revision of the maximum limit of admixture of lower class in the specifications of rice from 10% to 14%. Keeping in view the representations, it has been decided to accept rice in Andhra Pradesh with admixture of lower class upto 13% till to 31st March, 2000.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, Sir, we are happy that the Government have reviewed the decision of the Food Corporation of India and then decided to restore it, but surprisingly, the answer says that it will be allowed only up to March, 2000. Sir, this is a variety which is grown in at least six districts of Andhra Pradesh and this is classified as a super fine variety, and a lot of export is also taking place. Because of this downgradation of reducing the admixture from 14 per cent to 10 per cent, the price has come down and the farmers are put to hardships. I am happy that the Government have now reviewed it. But will they create it a permanent feature? Is there any problem in doing it? If there is a problem regarding the quality itself, will the Government think in terms of supplying a fine variety of seeds so that this problem of admixture doesn't arise?

श्री शांता कुमार : सभापति जी, जहां तक इस वैरायटी का सवाल हैं, इसको डाऊन ग्रेड नहीं किया है। चावल की तीन वैरायटी थीं- फाइन, सुपर फाइन और कॉमन, उनको अब दो में कर दिया है और यह जो 1001 ग्रेड हैं, अब यह ग्रेड ए में आ गया हैं। पहली बात तो यह है कि डाऊन ग्रेड हमने नहीं किया है। सभापति जी, हमारे सामने समस्या यह है कि वर्ष 1997-98 में स्पेसिफिकेशन रिलेक्स की गई थीं, जैसा कई बार मौसम की खराबी के कारण या कई बार राजनैतिक मौसम की खराबी के कारण होता है और आज स्थिति यह है कि रिलेक्स स्पेसिफिकेशन का 27 लाख टन च सवल हमारे पास ऐसा पड़ा हैं, जिसको लेने के लिए प्रदेश तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं सभापति जी, हमारे पास इस समय 3 लाख 80 हजार टन चावल ऐसा है, जो नॉन-इस्युएबल हैं,इसी कारण से कि जब लिया गया था स्पेसिफिकेशन रिलेक्स की गई थी या और कुछ कारण हुए । तो यह जो 3 लाख 80 हजार टन चावन हमारे पास पड़ा है, जो इस्यू नहीं किया जा सकता, उसको रखने के का खर्चा 60 करोड़ रूपए साल का हैं। इसलिए सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि स्पेसिफिकिशन रिलेक्स नहीं किए जाएंगे, गुणवत्ता के बारे में, क्वालिटी के बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह निर्णय सख्ती के साथ पालन करने की कोशिश की हैं।

सभापति जी, जहां तक आंध्र प्रदेश की इस वैराइटी का सवाल है, हमारे पास इस प्रकार की बातें आई कि यह विशेष वैराइटी हैं, पहले से सूचना नहीं मिली, किसान परेशानी में हैं, और इसलिए केवल इस वर्ष के लिए, जो 10 प्रतिशत हमने कर दिया था रिलेक्स एडमिनिज्ञटर्ड में, इसको इस वर्ष के लिए 13 प्रतिशत कर दिया हैं। सभापति जी, हमने इस वैराइटी के बारे में विशेष टेस्ट करवाए हैं और अब मैंे माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमने जो टेस्ट करवाए उसके मुताबिक भी 10 प्रतिशत से अधिक कोई जस्टिफिकेशन नहीं हैं। लेकिन, चूंकि

पहले 14 प्रतिशत था, समय पर नहीं बताया गया था और बहुत से माननीय सदस्यों ने भी इस बारे मे कहा, तो इस आधार पर केवल इस वर्ष के लिए 13 प्रतिशत किया हैं। अगले वर्ष हम रिलेक्स करने की स्थिति मे नहीं हैं।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, Sir, the Government have taken some positive action. I have already said that we are happy about it, but, at the same time, if it was allowed 14 per cent previously, that was also done only after conducting specific tests.

Now the Department is coming with an answer saying that we have got the test conducted and it is not allowed up to 13 per cent because there are no takers. I am not able to understand this and even appreciate this response. Sir, everywhere there is a demand for this variety of rice. Even this Ministry of the Government of India is giving rice to Orissa. They can as well supply this rice to the Orissa cyclone-affected people also. There are 3,80,000 tonnes of rice available. We have got a public distribution system in Andhra Pradesh also. In the State's local terminology, it is considered by the people as a super fine variety. I don't know what the view of the concerned Department is, and how suddenly it is changed. Will the Minister discuss this issue, in detail, with the Government of Andhra Pradesh and also the farmers' representatives? One thing should be appreciated. As it was not told earlier, the farmers have gdne for that and the Government is coming to their rescue. But, at the same time, abandoning the variety as such, or downgrading it, in whatever way you classify it, is not in the interest of the farming community.

श्री शांता कुमार : सभापति जी, मैंने पहले की कहा कि इस वैराइटी को डाउन ग्रेड नहीं किया हैं। मैं एक बात और सदन को बता देना चाहता हूं कि गेहूं में, बीट में पहले चार वैराइटी थीं, फिर दो की और अब एक कर है और इसी तरह चावल मे तीन से दो की हैं। सभापति जी, जितनी ज्यादा वैराइटी, जितनी ज्यादा फारमेलिटीज़ जितनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन होती हैं, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता हैं। स्पेसिफिकेशन इस ढंग से होती हैं- चावल की लम्बाई कितनी हैं, चौड़ाई कितनी हैं, उसका रेशो निकालों। अब उसमें जितनी फारमेलिटीज़ होती हैं, उतनी गड़बड़ उतना भ्रष्टाचार होता हैं। अब तो मंत्रालय यहां तक सोच रहा है कि चावल की तीन से दो वैराइटी की बजाए दो से भी एक वैराइटी कॉमन पर आया जाय, करॉमन की पैदावार भी ज्यादा होती हैं, ताकि उसमे कम से कम भ्रष्टाचार हो, कम से कमण गड़बड़ हो। आपने जैसे पूछा हैं, 1994-95 में दस प्रतिशत थी विद क्वालिटी कट 20 परसैंट, फिर 10 परसैंट एडमिस्टर्ड था,

फिर उसके बाद 14 हुई, अब धीरे-धीरे कम करते-करते उसको 10 परसैंट कर दिया गया हैं। सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि जब पैडी में 10 परसैंट ऐडमिस्टर्ड अलाऊ नहीं है तो राइस में 14 परसैंट कैसे होगा क्योंकि पेडी से राइस जब बनता है तो 70 परसैंट रह जाता है, तो 10 परसैंट यदि पैडी में है तो चावल बनने पर कम होने की संभावना हो सकती है बढ़ने की संभावना नहीं हो सकती। यदि इतना किया जाएगा तो एडल्ट्रेशन की अधिक संभावना हो जाएगी। टैस्ट भी हमने सारे करवा दिए हैं, टैस्ट्स की रिपोर्ट आ गई हैं, मैं माननीय सदस्य का टैस्ट्स की सारी रिपोर्ट भेजूंगा। आंध्र के मित्रों से बातचीत भी हो गई हैं, आन्ध्र के मुख्य मंत्री से भी मेरी बातचीत हो गई हैं मैने सारी बात उनको बता दी है और मेरी बात से वे भी कन्विंस हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस साल की विशेष परिस्थिति है और उस परिस्थिति के कारण हमने 13 परसैंट कर दिया, अगले साल नहीं कर सकेगे क्योंकि क्वालिटी को स्ट्रिक्टली मेंटेन करने का निर्णय सरकार ने कर लिया हैं।

SHRI YADLAPATI VENKAT RAO: Sir, our Chief Minister had written about this 1001 variety, umpteen number of times. The specification has been relaxed up to 13 per cent. It is good. This variety is an 'A' Grade variety and it is a widespread variety in Andhra Pradesh, especially, the first receipt. This relaxation is up to the end of 31st March, 2000, It should be extended further, otherwise, the farmers will experience a lot of hardships. I would request the hon. Minister to extend the period beyond 31.3.2000, to a further period of 5-6 months so that the farmers may dispose off the paddy.

श्री शांता कुमार : सभापति जी, मेरी बातचीत हो गई है और वे सेटिस्फाइड है कि इससे हमारा काम हो जाएगा।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to draw the attention of this House to an urgent matter. Sir, more than hundred youth belonging to the Assom Yuva Parishad are staging a dharna in the Jantar Mantar area. *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: I have not asked you to spGak on that. I thought you are putting a supplementary. *(Interruptions).* No, no. *(Interruptions)* Nothing on this. *(Interruptions).* Please sit down. Now, Papers to be laid on the Table. *(Interruptions)* I thought you wanted to put a question. This is not a question. *(Interruptions)* It is not a supplementary. Now, Papers to be laid on the Table.